# मुक्त व्यापार के आदर्शवाद से परे

लेखक -अरुण मायरा ( योजना अयोग के पूर्व सदस्य )

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II ( अंतर्राष्ट्रीय संबंध ) एवं III ( भारतीय अर्थव्यवस्था ) से संबंधित है।

द हिन्दू

25 अप्रैल, 2019

**"एक महत्वाकांक्षी 'रोजगार और आय नीति' अगली सरकार के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।"**

अमेरिका ने भारत के साथ व्यापार झड़प शुरू कर दी है। इसने भारत में इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है और वह चाहता है कि भारत अमेरिकी-निर्मित मोटरसाइकिलों पर शुल्क कम करे। इस बीच विश्व व्यापार संगठन सभी घटनाक्रमों पर अपनी नजर जमाये हुए है। यह एक व्यापारिक शासन को फिर से लागू करने के लिए मूलभूत सिद्धांतों को प्रतिपादित करने का समय है, जो सभी के लिए उचित साबित होगा।

**मुक्त व्यापार पर**

मुक्त व्यापार के लिए वृहद्-आर्थिक मामला यह है कि यदि प्रत्येक व्यक्ति केवल वही करेगा जो वह सभी से बेहतर करता है और सभी एक-दूसरे के साथ व्यापार करेंगे, तो सभी का कल्याण बढ़ेगा। इसके अलावा, वैश्विक आर्थिक आकार बड़ा होगा क्योंकि इसमें कोई अक्षमता नहीं होगी। समस्या यह है कि वर्तमान में दुनिया में बहुत से लोग वही कर रहे हैं जो दूसरे उनसे बेहतर कर सकते हैं। अर्थशास्त्रियों के आदर्श राज्य तक पहुँचाने के लिए बहुत से लोगों को वह करना बंद करना होगा, जो वे कर रहे हैं तथा कुछ और करने के लिए सीखना होगा।

डॉनी रोड्रिक ने अनुमान लगाया है कि वैश्विक आय में समग्र वृद्धि की प्रत्येक इकाई के लिए आय की छह या सात इकाईयों में चारों ओर फेरबदल करना होगा। इसके अलावा, इस सिद्धांत के अनुसार, लोगों को वह उत्पादन शुरू नहीं करना चाहिए जो दूसरे पहले से ही उत्पादित कर रहे हैं, क्योंकि वे तब तक कम कुशलता से उत्पादन करेंगे जब तक कि वे इसे अच्छी तरह से करना नहीं सीखते। मुक्त व्यापार के इस सिद्धांत के अनुसार, भारतीयों को यह सीखने की जहमत नहीं उठानी चाहिए कि देश के स्वतंत्र होने पर ट्रकों, बसों और दोपहिया वाहनों का उत्पादन कैसे किया जाए। उन्हें अमेरिकी, यूरोपीय और जापानी कंपनियों से आयात करना जारी रखना चाहिए था।

मुक्त व्यापार के सन्दर्भ में निरपेक्षवादियों का कहना है कि अन्य देशों के उत्पादों के आसान आयात से उपभोक्ता कल्याण बढ़ता है। उपभोक्ता हर जगह आयात बाधाओं को कम करने वाली नीतियों का स्वागत करते हैं क्योंकि इससे उनकी दुकानों में उत्पाद आता है। मिल्टन फ्रीडमैन के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, निर्यात कंपनियों की मद्द करते हैं और आयात नागरिकों की मद्द करते हैं। इसलिए, मुक्त व्यापार का प्रतिरोध उपभोक्ताओं से नहीं होता है। यह आमतौर पर उन कंपनियों से आता है जो प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती हैं अर्थात् कम विकसित देशों की कंपनियां जो अपने देश के बुनियादी ढांचे में सुधार होने तक प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं हैं।

**रोजगार में वृद्धि**

हालांकि, आसान आयात से लाभ उठाने के लिए, नागरिकों को उपलब्ध उत्पादों और सेवाओं को खरीदने के लिए आय की आवश्यकता होती है। इसलिए उन्हें रोजगार की आवश्यकता है जो उन्हें पर्याप्त आय प्रदान करेगी। अपने नागरिकों के कल्याण के लिए जिम्मेदार किसी भी सरकार को देश में रोजगार के विकास के बारे में चिंतित होना पड़ता है।

घरेलू उत्पादक रोजगार दे सकते हैं। इसलिए एक विकासशील देश को अपने प्रतिस्पर्धी लाभों के आधार पर घरेलू उत्पादन

के विकास में तेजी लाने के लिए एक अच्छी 'औद्योगिक नीति' की आवश्यकता है और उन क्षमताओं को विकसित करके, यह उन देशों के उत्पादकों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है जो पहले विकसित हुए थे।

जब 1990 के दशक में 'नो बैरियर्स टू फ्री ट्रेड' आंदोलन वाशिंगटन की सहमति से अपने चरम पर था, तो औद्योगिक नीति की अवधारणा, जो घरेलू उद्योगों के 'संरक्षण' के विचार से जुड़ी हुई थी, कमजोर पड़ गयी। भारत ने 1990 के दशक में आयात को उदार बनाया और तब से भारतीय उपभोक्ताओं को दुनिया भर से उपलब्ध विभिन्न प्रकार के उत्पादों से बहुत लाभ हुआ। हालांकि, 2009 तक जब दूसरी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार बनी, तो भारतीय विनिर्माण उद्योगों की कमजोरी एक बड़ी चिंता बन गई थी।

1990 में भारत और चीन में विनिर्माण क्षेत्र की तुलनात्मक क्षमता थी। 2009 तक, चीन का विनिर्माण क्षेत्र भारत की तुलना में 10 गुना बड़ा था और इसका पूंजीगत उत्पादन क्षेत्र 50 गुना बड़ा था। भारतीय बाजार न केवल चीन के हाथ से बनाये उपकरण और खिलौनों से भरा हुआ था, बल्कि चीन, भारत (और दुनिया भर में भी) को उच्च तकनीक वाले बिजली और दूरसंचार उपकरण भी बेच रहा था।

संकेत पहले से ही दिखाई दे रहे थे कि भारत की प्रभावशाली जीडीपी वृद्धि भारत की बड़ी युवा आबादी के लिए पर्याप्त रोजगार पैदा नहीं कर रही थी। सरकार के कुछ लोगों ने घरेलू उत्पादन की वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए एक 'औद्योगिक नीति' की आवश्यकता की सिफारिश की। हालांकि, कई भारतीय अर्थशास्त्रियों के साथ विश्व बैंक और यू.एस. ने इस विचार को सही नहीं ठहराया। इनके अनुसार, 'औद्योगिक नीति' सोवियत युग की योजना से जुड़ा एक पिछड़ा विचार था। अगर भारतीय उद्योग नहीं बढ़ रहा था, तो यह इसलिए था क्योंकि भारत ने 'पर्याप्त सुधार' नहीं किया था अर्थात् भारत को व्यापार बाधाओं को और कम करना चाहिए तथा सरकार को उद्योग के रास्ते से बाहर निकलना चाहिए।

**अगला चरण**

2019 तक, यह स्पष्ट हो गया है कि भारत के नीति-निर्माताओं को भारतीय नागरिकों के लिए आय बढ़ाने के अवसरों का निर्माण करने के लिए आर्थिक विकास के लिए एक रास्ता खोजना होगा। रोजगार और आय भारतीय नागरिकों के लिए सबसे अधिक दबाव वाले मुद्दे हैं, जिनकी सभी नागरिक चुनाव के वक्त अगली सरकार से उम्मीद करते हैं। सभी पार्टियां सार्वभौमिक बुनियादी आय के विभिन्न संस्करणों के बारे में जल्दबाजी कर रही हैं। ऐसा दृष्टिकोण आर्थिक रूप से टिकाऊ होगा इसकी संभावना कम ही है। इसलिए एक महत्वाकांक्षी रोजगार और आय नीति अगली सरकार के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

जहाँ भारत वैश्विक बाजारों के बड़े शेयरों पर अपना वर्चस्व चाहता है, वहीं भारत को खुद की अरबों से अधिक नागरिकों की अर्थव्यवस्था लाखों उद्यमों के विकास के लिए एक प्रेरणा बन सकती है। यदि नागरिक अधिक कमाते हैं, तो वे अधिक खर्च करेंगे। रोजगार और आय नीति को जहाँ निवेश की आवश्यकता होती है वहाँ औद्योगिक नीति का मार्गदर्शन करना चाहिए और उन निवेशों से यह भी अपेक्षा करनी चाहिए कि वे युवा भारतीयों के लिए आय के अधिक अवसर पैदा करें।

उद्योग के दायरे को व्यापक करके उन सभी क्षेत्रों को शामिल करना चाहिए, जो भारत के प्रतिस्पर्धात्मक लाभों पर निर्माण कर सकते हैं। उदाहरण के लिए पर्यटन और आतिथ्य उद्योग भारत की संस्कृतियों और प्राकृतिक सुंदरता की उल्लेखनीय विविधता का लाभ उठाते हुए, देश के सभी हिस्सों में लाखों छोटे उद्यमों का समर्थन करने की क्षमता रखते हैं। बड़ी संख्या में प्रशिक्षित युवाओं द्वारा भारत के प्रतिस्पर्धात्मक लाभ का निर्माण करके और छोटे उद्यमों की पहुंच बढ़ाने के लिए डिजिटल तकनीकों के साथ विनिर्माण और सेवाएं कई घरेलू और निर्यात अवसर प्रदान कर सकती हैं जिसका भारत ने अब तक लाभ नहीं उठाया है।

भारत अपने इतिहास से सीख सकता है। पूर्व-उदारीकरण युग में सरकार की यह पहल थी कि उत्पादन और प्रौद्योगिकी को चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रमों में स्वदेशी होना चाहिए और भारत का ऑटोमोबाइल क्षेत्र भारतीय उपभोक्ताओं को अच्छे उत्पाद प्रदान करने में सक्षम भी था। यह अब व्यापक घरेलू आपूर्ति श्रृंखलाओं में लाखों लोगों को रोजगार और आय प्रदान करता है। इसके अलावा, भारतीय ऑटो-घटक निर्माता और वाणिज्यिक वाहन निर्माता दुनिया के सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी बाजारों में निर्यात करते हैं।

इसके विपरीत, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में गिरावट आई है, जबकि चीन का इस संदर्भ में विकास हुआ है। भारत ने 1996 में विश्व व्यापार संगठन के सूचना प्रौद्योगिकी समझौते पर हस्ताक्षर किए और आईटी से संबंधित निर्मित उत्पादों पर आयात शुल्क

घटाकर शून्य कर दिया। चीन कुछ समय के लिए इससे पीछे हट गया, जब तक कि उसका इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र मजबूत नहीं हुआ। अब अमेरिका और यूरोप अपने बाजारों में चीन के दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिक सामानों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं।

अंत में, मुक्त व्यापार आदर्शवाद की आड़ में अमीर देशों में कंपनियों के निर्यात में बाधाओं को कम करने के बजाय सभी देशों में, विशेष रूप से गरीब देशों में, नागरिकों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए डब्ल्यूटीओ के शासन में मरम्मत करने की आवश्यकता है। और सार्वभौमिक बुनियादी आय के गणित से विचलित भारतीय अर्थशास्त्रियों को आर्थिक विकास के मूल सिद्धांतों पर लौटना चाहिए अर्थात् नई क्षमताओं के विकास के साथ उत्पादक कार्यों से आय अर्जित करने के अवसर पर अधिक ध्यान देना चाहिए। एक कल्पनाशील औद्योगिक नीति द्वारा समर्थित एक मजबूत आय और रोजगार नीति को भारत की व्यापार नीति का मार्गदर्शन करना चाहिए।

## GS World टीम...

### मुक्त व्यापार

**चर्चा में क्यों?**

- हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनाल्ड ट्रंप ने भारत पर अमेरिकी सामानों पर भारी-भरकम शुल्क लगाने का आरोप लगाते हुए अपने अधिकारियों को जवाबी कार्रवाई करने के लिए कहा है।
- भारत को 'सर्वाधिक शुल्क लगाने वाले देशों में से एक' करार देने वाले ट्रंप ने भारत के साथ अमेरिकी व्यापार को 'मूर्खता से भरा कारोबार' करार दिया है।
- इससे पहले भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि वह भारत का नाम उन देशों की सूची से बाहर कर देंगे, जो सामान्य कर-मुक्त प्रावधानों (जीएसपी) कार्यक्रम का लाभ उठा रहे हैं।
- यह लाभ उन उत्पादों पर उठाया जाता है जिनका निर्यात अमेरिका को किया जाता है।
- अमेरिका के अनुसार उसने यह कदम भारत पर उचित व्यापारिक सहयोग नहीं करने के कारण उठाया है।

**क्या है?**

- मुक्त व्यापार का सर्वप्रथम अभिलेखाकरण एडम स्मिथ द्वारा 1776 में लिखी अपनी उत्कृष्ट पुस्तक 'द वेल्थ ऑफ नेशन्स' में किया गया है।
- मुक्त व्यापार दो या दो से अधिक देशों के बीच बनाई गई वह नीति है जो साझेदार देशों के बीच वस्तुओं या सेवाओं के असीमित निर्यात या आयात की अनुमति देती है।
- व्यापार समझौते तब होते हैं जब दो या दो से अधिक राष्ट्र आपस में व्यापार की शर्तों पर सहमत होते हैं। ये समझौते आयात और निर्यात पर लगाए गए टैरिफ और अधिभारों का निर्धारण करते हैं। सभी व्यापार समझौते अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करते हैं।
- ऐसे समझौते करने के लिये देशों या देशों के समूहों को डब्ल्यूटीओ के दायरे में आने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिये डब्ल्यूटीओ के नियमों से अगर उन्हें कहीं रुकावट हो रही हो तो वे एफटीए (FTA) के सहारे भी आगे बढ़ सकते हैं।
- मुक्त व्यापार टैरिफ को समाप्त करता है तथा कॉर्पोरेशन को विदेशी बाजारों में अधिक प्रतिस्पर्द्धी बनाता है।
- एफटीए में आमतौर पर वस्तुओं (जैसे-कृषि या औद्योगिक उत्पाद) या सेवाओं के व्यापार (जैसे-बैंकिंग, निर्माण, ट्रेडिंग इत्यादि) को कवर किया जाता है।
- एफटीए बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR), निवेश, सरकारी खरीद और प्रतिस्पर्द्धी नीति आदि जैसे अन्य क्षेत्रों को भी कवर कर सकता है।

**आवश्यकता क्यों?**

- टैरिफ और कुछ गैर-टैरिफ बाधाओं को खत्म करने से एफटीए भागीदारों की एक-दूसरे के बाजारों में पहुँच आसान होती है।
- निर्यातक बहुपक्षीय व्यापार उदारीकरण के लिये एफटीए को पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें गैर-एफटीए सदस्य देश के प्रतिस्पर्द्धियों पर अधिमान्य सहूलियत मिलती है। उदाहरण के लिये, आसियान के मामले में, आसियान का भारत के साथ एफटीए है लेकिन कनाडा के साथ नहीं।
- एफटीए से बाहर विदेशी निवेश में वृद्धि की संभावना होती है, जबकि मुक्त व्यापार समझौते मुक्त व्यापार और निवेश प्रवाह को बढ़ावा देते हैं।
- एफटीए व्यापार उत्पादकता और नवाचार को प्रोत्साहित करते हैं। इससे क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा मिलता है।
- एफटीए विकासशील देशों की मद्द कर सकते हैं तथा इससे व्यापार का माहौल गतिशील होता है।

## संभावित प्रश्न ( प्रारंभिक परीक्षा )

**1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:-**

1. एफटीए में आमतौर पर वस्तुओं या सेवाओं के व्यापार को कवर किया जाता है।
2. एफटीए बौद्धिक संपदा अधिकार, निवेश, सरकारी खरीद और प्रतिस्पर्द्धी नीति आदि जैसे अन्य क्षेत्रों को कवर कर सकता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

**2. 'मुक्त व्यापार' के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:-**

1. सर्वप्रथम इसका उल्लेख एडम स्मिथ द्वारा किया गया था।
2. यह दो या दो से अधिक देशों के मध्य बनाई गई वह नीति है, जो साझेदार देशों के बीच वस्तुओं या सेवाओं के असीमित निर्यात या आयात की अनुमति देती है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

**1. Consider the following statements-**

1. Generally trade of goods and services is covered in FTA.
2. FTA can cover Intellectual property Right, investment procurement and competitive policies etc.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1
(b) Only 2
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

**2. Consider the following statements regarding 'Free Trade'-**

1. It was first mentioned by Adam smith.
2. It is that policy between two countries which enables the unlimited export and import of goods and services.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1
(b) Only 2
(c) 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

## संभावित प्रश्न ( मुख्य परीक्षा )

**प्रश्नः- हाल ही में अमेरिका और भारत के मध्य व्यापार के क्षेत्र में बढ़ते विवाद को देखते हुए भारत को किस प्रकार की रणनीति अपनानी चाहिए? चर्चा कीजिए। ( 250 शब्द )**

**Q. Observing the increasing dispute between India and America in the trade sector, which type of strategy should India adopt. (250 Words)**

**नोट :** 24 अप्रैल को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(a), 2 (a) होगा।